



2026:AHC:67661-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 413 बी.एन.एस.एस. के तहत आपराधिक अपील संख्या - 192 वर्ष 2026

बजरूल खान अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार बिंद, मोहित कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 43

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह-I

अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

धारा 413 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत अपील III अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), फर्रुखाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-57/2017 (राज्य बनाम आजम खान और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.02.2026 के खिलाफ दायर की गई है, जो धारा 302/34 भ०द०वि०, थाना-कांपिल, जिला फर्रुखाबाद के तहत दायर की गई है। अपने उपरोक्त निर्णय के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने आरोपी/प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि लगभग 11 वर्ष की आयु का हसरूल, जो अपीलकर्ता का बेटा था, 2.8.2016 को सुबह 11 बजे से लापता था। हसरूल (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) का शव 3.8.2016 को दोपहर 1:30 बजे एक इरशाद के उपवन में पाया गया था। प्रतिपक्षियों को संदिग्ध के रूप में नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और परिणामस्वरूप, आरोपी / प्रतिपक्षियों के खिलाफ धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



302/34 भ०द०वि० के तहत केस अपराध संख्या-232 वर्ष 2016 दर्ज किया गया था। जांच के बाद, शव को 4.8.2016 को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था और 4.8.2016 को सुबह 10:30 बजे शव का शव परीक्षण किया गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोटों का उल्लेख किया गया था, जो इस प्रकार हैं: -

"बाहरी परीक्षा - मृतक औसत कद का था, और गैस जमा होने के कारण शरीर विकृत हो गया था। मुंह खुला था; दोनों आंखें उभरी हुई थीं, और जीभ भी बाहर की ओर उभरी हुई थी। कई फफोले मौजूद थे। त्वचा में छीलने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, और कीड़े मौजूद थे। शरीर से दुर्गंध आ रही थी। कठोरता मोर्टिस पूरे शरीर में पूरी तरह से कम हो गई थी। पूर्व-मॉर्टम चोटों में शामिल हैं: 1- 4 सेमी x 1 सेमी मापने वाला एक क्षत-विक्षत घाव, जो हड्डी की गहराई तक फैला हुआ है, जो सिर के ऊपरी दाईं ओर, दाहिने कान से 11 सेमी ऊपर स्थित है। विच्छेदन करने पर, खोपड़ी की पार्श्विका हड्डी टूटी हुई पाई गई। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली फट गई थी और उसका रंग लाल हो गया था। 2- 3 सेमी x 0.5 सेमी मापने वाला एक घाव जो मांसपेशियों के ऊतकों की गहराई तक फैला हुआ है, जो दाहिनी जांघ के निचले पूर्वकाल पहलू पर स्थित है। 3- 4.5 सेमी x 0.5 सेमी मापने वाला एक घाव, जो गर्दन के निचले दाईं ओर स्थित मांसपेशियों के ऊतकों की गहराई तक फैला हुआ है। 4- छाती के ऊपरी बाईं ओर 5 सेमी x 2 सेमी मापने वाला एक नीला घाव मौजूद था। आंतरिक परीक्षा - फेफड़ों में अपघटन शुरू हो गया था। दिल खाली था। पेट में 80 ग्राम अर्ध-पचने वाला खाद्य पदार्थ था। दोनों गुर्दे में अपघटन शुरू हो गया था। उनकी राय में, मृतक की मृत्यु लगभग दो दिन पहले हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त पूर्व-मॉर्टम चोटों और आघात के परिणामस्वरूप हुआ था। मृतक के शरीर को शर्ट और अंडरवियर पहना हुआ था। शव परीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक दस्तावेजों और जब्त वस्तुओं के सीलबंद बंडल के साथ कांस्टेबल पंकज कुमार को सौंप दिया गया।

चोटों से संकेत मिलता है कि मृतक की मौत हत्या की प्रकृति की थी। जांच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और मामले को मुकदमे के लिए सत्र अदालत में सौंप दिया



गया और आरोपी के खिलाफ सत्र परीक्षण संख्या-57/2017 दर्ज की गई। आरोपियों पर धारा 302, 34 भ०द०वि० के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपी ने आरोप से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

अभियोजन पक्ष के मामले की नींव यह है कि अ०सा०-2 और अ०सा०-3 ने आरोपी को 2.8.2016 को मृतक को लाठियों से पीटते हुए देखा था। अ०सा०-2 और अ०सा०-3 द्वारा यह कहा गया था कि जब उन्होंने आरोपी को मृतक को पीटते हुए देखा तो उन्होंने आरोपी को चुनौती दी थी और मृतक को पीटने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी, जिसके बाद आरोपी ने गवाह को धमकी दी और चला गया। गवाह डर गए और अपीलकर्ता यानी मृतक के पिता को सूचित नहीं किया। पहले सूचनाकर्ता, यानी, अपीलकर्ता को अ०सा०-1 के रूप में बताता है कि अ०सा०-2 और अ०सा०-3 ने उसे सूचित किया था कि आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी थी। अपने साक्ष्य में, अ०सा०-2 और अ०सा०-3 ने यह भी कहा है कि जब गवाह द्वारा उन्हें चुनौती देने के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गए, तो गवाह मृतक के पास गया था और देखा था कि वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन उन्होंने मृतक को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, भले ही मृतक अभी भी जीवित था क्योंकि वे प्रतिपक्षियों से डरते थे। गवाह पूछताछ के दौरान मौजूद थे और शव परीक्षण के दौरान भी मौजूद थे और मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लिया था। विवेचनाधिकारी द्वारा गवाहों से पूछताछ की गई और घटना के 10 से 11 दिन बाद धारा 161 द०प्र०स० के तहत अपने बयानों में विवेचनाधिकारी को उपरोक्त तथ्य का खुलासा किया। यह भी ध्यान दिया जाता है कि अपनी गवाही में, अ०सा०-2 और अ०सा०-3 ने कहा है कि जब उन्होंने मृतक को पीटने वाले अभियुक्तों को चुनौती दी, तो मौके पर हंगामा हुआ और कई ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए थे। हालांकि, अ०सा०-2 और अ०सा०-3 के अलावा घटना का कोई अन्य गवाह नहीं है।

अ०सा०-2 और अ०सा०-3 की गवाही पर विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अविश्वास किया है कि उनकी गवाही में वर्णित उनका आचरण सामान्य मानवीय व्यवहार के खिलाफ था, इसलिए इसे स्वीकार करने के योग्य नहीं है। उपरोक्त के अलावा, तथ्य यह है कि घटना के 10 से 11 दिन बाद विवेचनाधिकारी द्वारा गवाहों से पूछताछ की गई थी थी और धारा 161 द०प्र०स० के तहत उनके बयान बहुत देरी के बाद दर्ज किए गए थे,



आरोपी को दोषी ठहराने के लिए गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन में कोई विकृति नहीं है ताकि हमें सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अभिलेखों बुलाने के लिए राजी किया जा सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जांच एजेंसी द्वारा हमले का हथियार बरामद नहीं किया गया था और पुलिस द्वारा तलाशी पर या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी के प्रकटीकरण बयान पर हथियार की बरामदगी के संबंध में अपील में कोई आधार नहीं उठाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर साक्ष्य और सामग्री प्रदर्शनों का चार्ट, जैसा कि निर्णय में उल्लेख किया गया है, किसी भी हथियार की बरामदगी नहीं दिखाता है और उक्त तथ्य को अपील ज्ञापन में चुनौती नहीं दी गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमें अ०सा०-1 और अ०सा०-2 की अविश्वसनीयता के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन में कोई विकृति या कोई अन्य अवैधता नहीं मिलती है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक बोधगम्य दृष्टिकोण है और सबूतों पर आधारित है। प्रस्तुत अपील में तथ्य या कानून या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन के संबंध में कोई आधार नहीं उठता है।

उपरोक्त सभी कारणों से, हम मामले के अभिलेखों को तलब करने के बाद अपीलकर्ता के कहने पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का मामला नहीं मानते हैं।

अपील को सरसरी तौर पर **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद फाइल को अभिलेखों में भेज दिया जाए।

मार्च 31, 2026

विपाशा

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)